

अब कृषि मंत्रालय का नाम होगा कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय



69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

ध्रुव कुमार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कृषि मंत्रालय अब कृषि के अलावा किसानों की भलाई से जुड़ी अन्य जिम्मेदारियां भी वहन करेगा। इसके लिए कृषि मंत्रालय का नाम बदलकर कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय रखा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका एलान किया।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'साठ साल में हमने कृषि के आर्थिक पहलू पर बल दिया। मंत्रालय का नाम भी कृषि मंत्रालय रखा, लेकिन कृषि मंत्रालय का जितना महत्त्व है उतना ही महत्त्व किसान के कल्याण का भी है। अकेले कृषि विकास की बात ग्रामीण जीवन के लिए अधूरी है। वह पूर्ण तब होगी जब किसान

कल्याण को भी इसमें जोड़ा जाएगा। लिहाजा, अब कृषि मंत्रालय को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा। आने वाले दिनों में कृषि के लिए जैसी योजना बनेगी वैसी ही योजना किसान कल्याण के लिए भी बनेगी, ताकि किसान को व्यक्तिगत जीवन में जो समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, सरकार उनमें मदद करने का प्रयास कर सके।'

नई यूरिया नीति बनाई

प्रधानमंत्री ने किसानों के हित में खाद का उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों की चर्चा भी की। उन्होंने कहा, 'पूर्वी भारत में चार यूरिया कारखाने बंद पड़े थे। वहां नौजवान बेरोजगार थे। किसान परेशान हो रहा था।

- प्रधानमंत्री ने किया एलान, खेती के सथ उत्पादकों के कल्याण के लिए भी काम करेगा मंत्रालय
- नीम की कोटिंग से केमिकल फैक्ट्रियों में यूरिया डायवर्जन रुका, किसी और काम नहीं आएगी खाद
- नई यूरिया नीति से गोरेखपुर, बरेली, तालचर और सिंदरी खाद कारखानों का पुनर्जीवन शुरू

सपने साकार करने को उठे कदम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, 'किसान को पानी चाहिए, बिजली चाहिए। उस सपने को पूरा करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमने तय किया है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पचास हजार करोड़ रुपये लगाया जाएगा। हम पानी बचाओ, ऊर्जा बचाओ, खाद बचाओ मंत्र को लेकर चल रहे हैं। हमें कृषि जीवन में आंदोलन खड़ा करना है। लिहाजा, 'पर ड्रॉप मोर ड्रॉप' यानी एक-एक बूंद से अधिकतम फसल के काम को आगे बढ़ाने और इस पर धन खर्च करने की दिशा में आगे बढ़ें। पिछले दिनों ओले गिरे तो 30 फीसद नुकसान पर भी हमने किसानों को मुआवजा दिया। साठ साल में ऐसा कभी नहीं हुआ।'

इसलिए हमने नई यूरिया नीति बनाई और गोरेखपुर, बरेली, तालचर और सिंदरी के फर्टिलाइजर कारखानों को पुनर्जीवित करने के लिए कार्य कर रहे हैं।'

खाद आपूर्ति में गड़बड़ी सुधारी

खाद आपूर्ति में गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि अभी तक 15-25 फीसद यूरिया केमिकल फैक्ट्रियों में चला जाता था। लिहाजा हमने यूरिया में नीम की कोटिंग का काम शुरू कराया है। अब यूरिया खेती के सिवा और किसी काम में नहीं आ सकता। किसान को जितना चाहिए, उतना मिलेगा। नीम कोटिंग के कारण दस फीसद कम यूरिया के उपयोग से भी पूरा लाभ मिलेगा।

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, निदेशक कार्यालय
2. निजी सचिव, संयुक्त निदेशक (प्रसार)
3. निजी सचिव, संयुक्त निदेशक (कानून/संचान)
4. निजी सचिव, आपूर्ति/खाद संयुक्त निदेशक (श्रीधर)
5. प्रजारी, पी. एम. डी.
6. प्रजारी, कैटेट
7. प्रजारी, ए. के. एम. यू.

सुनीता गुप्ता

17/8/15

प्रजारी पत्रिका एवं समाचार पत्र
अनुभाग